

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-598/2010/टोंक

श्रीमती कम्मो पत्नी श्री मोहम्मद रफीक उर्फ कालू खां  
जाति मुसलमान निवासी तालकटोरा तहसील व जिला टोंक

....प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक टोंक
2. बजरंगलाल पुत्र भूरा निवासी ग्राम तुम्बीपुरा तहसील व जिला टोंक
3. सूरजमल पुत्र भूरा निवासी ग्राम तुम्बीपुरा तहसील व जिला टोंक
4. फूला पुत्री भूरा निवासी ग्राम तुम्बीपुरा तहसील व जिला टोंक ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री गिरिश शर्मा

अभिभाषक

....प्रार्थीया की ओर से

श्री आर.के.खदाव

उप-राजकीय अभिभाषक

....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

नाम तर्क

...अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4

निर्णय दिनांक : 08.10.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 21.08.2008 प्रकरण संख्या 76/2007 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक टोंक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण बजरंग लाल व सूरज मल पुत्र भूरा व श्रीमती फूला पुत्री भूरा ने खाता नं. 72 की भूमि काश्त ख.नं. 71 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म भूमि बारानी अव्वल व ख.नं. 75 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा बारानी अव्वल कुल दो किता कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा बारानी अव्वल लगानी 8 रू 71 पैसे वाके ग्राम शकुरपुरा उर्फ कचौलिया तहसील टोंक में स्थित भूमि व संयुक्त खाता नं 74 की भूमि काश्त ख.नं. 72 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म भूमि बारानी अव्वल लगानी 9 य 39 पैसे वाके ग्राम शकुरपुरा उर्फ कचौलिया तहसील एवं जिला टोंक में स्थित भूमि में से खाता नं 72 का सम्पूर्ण रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा व खाता नं. 74 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा में से 1/2 प्रार्थीया के पक्ष में विक्रय कर पंजीयन हेतु दिनांक 01.07.04 को उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक ने दिनांक

01.07.04 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर दस्तावेज प्रार्थीया को लौटा दिया। प्रकरण में आंतरिक लेखा जांच दल, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा यह आक्षेप लिया गया कि दस्तावेज के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के आधार पर उक्त खसरे सडक पर स्थित होने के कारण डी.एल.सी. के अनुसार शकुरपुरा एन.एच. 12 की निर्धारित दर 1,27,600/- की दर से गणना अपेक्षित है। क्रय की गई भूमि 10.425 बीघा का मूल्य 13,30,230/- पर मुद्रांक कर आदि वसूल किया जाना चाहिए। इस आधार पर अंकेक्षण दल ने कमी मुद्रांक 51,513/-, कमी पंजीयन शुल्क 9,362/- रु कुल वसूल योग्य राशि 60,875/- रु निर्धारित की। उपपंजीयक ने वसूली हेतु रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निगरानीधीन निर्णय दिनांक 21.08.2008 पारित करते हुए अन्तर मुद्रांक कर 51,513/- रु, कमी पंजीयन शुल्क 9,362/- रु, शास्ति 125/- रु. कुल वसूल योग्य राशि 61,000/- रु निर्धारित की जिसके विरुद्ध प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 का नाम प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर इस आधार पर तर्क किया गया कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष वांछित नहीं है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने यह भी कथन किया कि रेफरेन्स में मुख्य बिन्दु क्रय की गई कृषि भूमि सडक पर स्थित होने का बिन्दु निहित था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका देखकर ही निर्णित किये जाने योग्य था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने तो मौका देखा है व न ही इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष दिया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण कि उन्हें निर्णय की जानकारी वसूली नोटिस आने पर हुई, विश्वास योग्य होने के कारण एवं निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानियां अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही साइक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित आदेश पारित किया है, जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। पीठासीन अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally ceases. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as

avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थीया को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए उभयपक्ष को सूचित करते हुए मौका निरीक्षण कर पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.11.2018 को पेश हों। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश है कि अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 को भी नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

12. निर्णय सुनाया गया।

( नरेश्वराम )  
सदस्य